श्री नत्था सिंह : उपसभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य जसवंत सिंह ने बताया था कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में 11 जिले हैं, रेगिस्तान हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को थोड़ा-सा अपना सुझाव देना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान में भी दो-तीन जिले, जैसे-भरतपुर है, वहां बाढ़ आई और रेगिस्तान जो हैं; कई हजार बीघा जमीन में बने। इसलिए पूर्वी राजस्थान, जैसे भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर के लिए कुछ करेंगे ?

राव बीरेंद्र सिंह : भरतपुर और अलवर में बाढ़ की वजह से कोई जमीन रेगिस्तान नहीं बनी, कोई भूमि डेजर्ट नहीं बनी। यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

Rural Employment Generation

*284. SHRI CHATURANAN MISHRA†
SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a successive drop in the rural employment generation during the last three years;

(b) if so, what is the comparative drop in the rural employment generation during the last three years, year-wise;

(c) what are the factors responsible for the successive drop in the rural employment generation; and

(d) what is the estimated shortfall likely to occur in the rural employment generation as against the Sixth Five-Year Plan target?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Performance under National Rural Employment Programme during the last three years is as under:

Year	Employment generated (in million mandays)	Utilization of funds (in crores)	Unit cost of employment per mandays generation (in Rs.)
1981-82	354·52	317·71	8·96
1982-83	351·20	394·73	11·24
1983-84	302·76 (Provisional)	393·46 (Provisional)	13·00

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chaturanam Mishra.

The reduction in employment generation is mainly on account of the introduction of the provision of non-wage component up to a ceiling of 40 per cent of the cost of work in the year 1981-82 (this ceiling was raised to 50 per cent from middle of 1983-84); stress on taking up durable works, and the upward revision of minimum wages payable to workers in most of the States. As a result of these factors, there has been a progressive increase in the unit cost of generation of per manday of employment.

(d) Against the Sixth Plan, provision of Rs. 1620 crores, the total expenditure under NREP up to 1983-84 in the first four years of the Plan is Rs. 1323.43 crores. At this rate it is expected that the Plan provision will be exceeded by the end of 1984-85. The Sixth Plan target for generation of mandays was fixed at 1500 million to 2000 million mandays. Against this in the first four years of the Plan ending 31st March, 1984, 1422.06 million mandays have already been generated. The target for 1984-85 is generation of 309.13 million mandays. Thus the achievements are expected to meet the Plan Projections.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है, उससे स्पष्ट है कि एन० आर० ई० पी० मातहत एम्प्लायमेंट जेनरेशन घटता जा रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। इस स्कीम के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि समाज के गरीब वर्ग को मदद पहुंचती है। इस बात में अवश्य मतभेद है कि शासक वर्ग कहता है कि इस योजना में 12 करोड खर्च कर दिया, लेकिन हम कहते हैं कि इतना नहीं किया। लेकिन इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि यह योजना अत्यधिक गरीबों की मदद के लिए है और ऐसी स्थिति में यह एम्प्लायमेंट जनरेशन भी घटती जा रही है, यह चिंता का विषय है। उस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि करीब 145 करोड़ रुपया भी अप्रैल, 1984 तक खर्च नहीं हो पाया और जहां तक 1984-85 का ताल्लुक है, 457 करोड़ से ज्यादा रुपया इस योजना में मंजूर किया गया था, जिसमें अभी तक जो सरकार के पास आंकड़े हैं, उसमें 39 करोड़ रुपया ही खर्च किया जा चुका है। यह लेटेस्ट फिगर उस सदन में दिया गया है। जहां तक बिहार की स्थिति है, बिहार जो सबसे दरिद्र राज्यों में है और भी भयानक है, उसमें तो अप्रैल, 1984 तक भी 26 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो सका, जो सारे देश में हाइएस्ट फिगर है, जो सबसे ज्यादा गरीब है, वहीं सबसे ज्यादा रुपया खर्च नहीं हो पाया। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा क्या इस बारे में सरकार कोई जांच कराएगी कि बिहार में खासकर और अन्य राज्यों में भी ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इससे समाज का सबसे निम्नतम वर्ग लाभान्वित होने वाला है। यही मेरा पहला प्रश्न है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय उपसभापति जी, यह माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है। यह बात सही है कि योजना शुरू करते वक्त मकसद यही था कि गरीबों को खासकर बिहार के गरीब लोगों को बिहार के इलाके में रोजगार मिले और उससे उनको मदद हो। यह योजना सन् 1980 में शुरू की गई। पहले यह योजना "फूड फार वर्क" के नाम से जानी जाती थी। उस वक्त हण्डरेड परसेंट फाइनेन्स केन्द्रीय सरकार देती थी। वर्ष 1981 से एन० आर० ई० पी० योजना शुरू हुई और इसमें स्टेट का शेयर भी शामिल किया गया, 50-50 परसेंट, 50 परसेंट केन्द्रीय सरकार देती है और 50 परसेंट स्टेट सरकार देती है। उस लिहाज से किन्हीं किन्हीं स्टेट में, जहां कम काम हो रहा है, जैसे बिहार की बात हमारे माननीय सदस्य ने की। यह सही है कि यह सब स्टेट

गवर्नमेंट पर मुनहसिर है जहां स्टेट गवर्नमेंट सही ढंग से काम करती है उस में भी उस को कठिनाइयां आती है। कई बार उनके पास पैसा नहीं होता कि उस में लगा सकें। तो उस में कुछ कमी हो जाती है और सुचारू रूप से जैसे उन को काम करना चाहिए वह नहीं कर पाती। जो मशीनरी यह काम करती है वह भी ढंग से काम करे और अगर वह डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सही ढंग से काम करती है तो काम अच्छा होता है। कई राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माननीय सदस्य की स्टेट में कुछ कमी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि कुछ ज्यादा काम उस में नहीं हो रहा है। वहां काम हो रहा है और उस को आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि कैसे उस को और आगे बढ़ाया जाय। कई बार तो स्टाफ भी कम होता है। उस के लिये हम प्राविजन कर रहे हैं और कुछ कर भी दिया है और थोड़े दिन के बाद इस योजना में आप को सुधार दिखायी देने लगेगा। और पैसा जो बच जाता है, खर्च नहीं होता उस की वजह यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है वह पूरी तरह से उस में लग नहीं पाता और इसलिये लगता है कि काम कम हो रहा है, पैसा कम खर्च हो रहा है। अब तक 1620 करोड़ रुपया जो इस प्लान के लिये इस में रखा गया था उस में से 1323 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 1985 तक के पूरे अप-टू-डेट फीगर्स नहीं हैं लेकिन चार सालों में इतना खर्च हो चुका है।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा था और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिहार में इस रुपये का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया और उन्होंने कहा कि यह दिक्कतें आती हैं। तो यह क्यों नहीं हो पाता आप क्या इस की जांच करायेंगी ? क्या आप यह बतायेंगी कि यह क्यों नहीं खर्च हो पाता ?

श्री उपसभापति : उन्होंने कहा कि 50 परसेंट उन को खर्च करना है और वह रुपया इकट्ठा नहीं कर पाती हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : यह सही नहीं है। क्या राज्य सरकार ने कभी बताया है कि उस के पास पैसा नहीं है ?

श्री उपसभापति : आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री चतुरानन मिश्र : यह योजना समाज के न्यूनतम वर्ग के लिये है।

श्री उपसभापति : आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री चतुरानन मिश्र : वहां तो किसी दूसरे दल की सरकार भी नहीं है। उन्हीं के दल की सरकार है और वह सरकार इस योजना के लिये रुपया न दे पाये यह तो बड़ी चिन्ताजनक बात है। इसलिये इस में आप को हमारी मदद करनी चाहिये और इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। और अगर आप भी मदद नहीं करते हैं...

श्री उपसभापति : आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा दूसरा सवाल है कि इस योजना का जो सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है उस का एक प्रधान कारण यह है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन—राज्यों का भी और यहां का भी—धनी वर्ग की तरफ ओरियेन्टेड है और गरीब लोगों के लिये जो स्कीम होती है उस का वह सही अनुपालन नहीं करते हैं और जो स्कीम चलायी जा रही है उस में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस लिये मैं दूसरा प्रश्न फिर पूछूंगा कि जिन के

लिये आप यह रुपया खर्च कर रहे हैं उन को यह मिल रहा है या नहीं या जाली स्कीम बना कर आप को दी जा रही है, इस की जांच आप करायेंगे या नहीं ? या रुपया खर्च हो गया केवल इस से ही आप को संतोष हो जायगा ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं उस में पहला सवाल तो उन्होंने यह किया कि रुपया खर्च नहीं हो रहा है और दूसरा सवाल यह कर दिया कि क्या हम इस से मुतमईन हैं कि पैसा खर्च हो जाय तो काम हो गया। तो यह अलग अलग दो सवाल हैं। जहां तक बिहार सरकार का सवाल है, आप जो फरमा रहे हैं मैं उस की जांच कराउंगी मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है। 25 परसेंट जो आकड़ें आते हैं मार्च या अप्रैल तक उन को देख कर प्रिज्यूम किया जाता है कि 25 परसेंट पैसा पाइपलाइन में होगा खर्च करने के लिए जो स्कीम के लिए खर्च हो रहा होगा। तो यहां अप-टू-डेट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जिले के एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सब चीजें मुनहसीर करती हैं कि वह किस तरह से इस स्कीम को चला रहा है। कई बार फंड की भी कमी होती है और दूसरी बात यह है कि जो स्कीमें हैं उन के अंदर जिस तबके को फायदा पहूंचाने की कोशिश की जा रही है वह जरूर पहूंच रहा है। इतनी बड़ी स्कीम जब कही चलती है तो उस में थोड़ी बहुत कहीं न कही कमी रहती है, लेकिन यह मान लेना कि सब कही भ्रष्टाचार है और सब काम बेइमानी से चल रहा है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी के आंकड़े के अनुसार रोजगार घटता जा रहा है और इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि "स्थायी स्वरूप के निर्माण कार्य आरम्भ करने पर बल तथा कई राज्यों में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में लगातार वृद्धि के कारण" मान्यवर, जहां तक मैंने समझा है रोजगार के अवसरों के लिए फूड फार वर्क का काम अनाज न देने के कारण हुआ है। जो शुद्ध गांव के आखिरी आदमी का काम था, जिससे गांवों में छोटे छोटी सड़कें, लिंक रोड बनाए गए हैं, उसको सरकार अस्थाई काम मानती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांवों में लोग कच्ची सड़कों से अस्थाई काम चला रहे हैं और अभी कई पंचवर्षीय योजनाओं के बनाए जाने के बाद भी जहां तक मेरा अनुमान है, आप पक्की सड़कों से हर एक गांव को नही जोड़ पायेंगे। मान्यवर, लिंक रोड, कच्ची सड़कें बनाने की तो बात छोड़ दीजिए, पुरानी जनता सरकार के जमाने में जो कच्ची सड़कें बन गईं, उन पर वही एक खाची मिट्टी डालकर उनकी मरम्मत नहीं हुई है और सारी सड़कें बरसात व धूल उड़ने से समाप्त होती जा रही हैं मैं चतुरानन मिश्र जी की इस राय से सहमत नहीं हूं कि काम नहीं हो रहा है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं। काम तो कर रही हैं, चाहे बनाने का हो या बिगाड़ने का या धूल उड़ाने का हो। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतना काम कर रही है कि सारी की सारी कच्ची सड़कें जो जनता सरकार में बनवाई गई थीं, अगर उनकी मामूली मरम्मत जो हो जाती तो तीन साल में तो काफी दिनों तक वे चलती। उनकी मरम्मत नहीं की गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कितने दिनों में आप पक्की सड़कों से हर एक गांव को जोड़ देंगे ताकि कच्ची बनाई गई सड़कों को उखाड़ने की जरूरत इनको न पड़े और

जल्दी नहीं कर सकते तो उन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करा रहे हैं जिसमें कि रोजगार के अवसर भी ज्यादा हो सकें और सड़कें भी बरकरार रहें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जनता पार्टी का मामला छेड़ ही दिया तो हम भी कहना चाहते है कि हमको इनकी सरकार से यही शिकायत थी कि उन्होंने कच्ची सड़कें बनाने पर ही जोर दिया इसलिए कि कह सकें कि इतनी सारी सड़कें बनाई। लेकिन न उनमें पुलिया हैं, न उनको सही रूप में जोड़ा गया है, नतीजा यह हुआ कि जो सड़कें बनाई गई उन्होंने बनाने के बजाय गांव के गांव बरबाद कर दिए। हमने इसलिए इसमें यह परिवर्तन किया है कि फूड फार वर्क का जो काम है जिसमें पहले अनाज देते थे, उसमें परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि जब इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसमें गांव का विकास तो हो, जनता पार्टी की तरह से काम न हो, जो काम हो वह मजबूत काम हो, इसलिए यह किया गया है कि 50 परसेंट तक मटीरियल कंपोनेंट पर, बेज और नान-वेज जो हैं उन पर खर्च किया जाए और काम पक्का हो, जो कच्चे रास्ते छोड़े गए हैं उनको पक्का करने में तो वक्त लगेगा।

श्री राम नरेश कुशवाहा : पक्की सड़कें तो बनाई ही नहीं गई हैं.... **(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : बस हो गया आपका उत्तर आ गया, श्रीमती आशमा चटर्जी।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE: Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any monitoring cell either at the district level or at the block level to study the progress of the work for which the State Government is receiving grants. Secondly, how many monitoring cells are there? Thirdly, is there any arrangement for the development of social forestry? Fourthly, are the rural people being encouraged to start small cottage industries with the natural resources available there?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जिन ने सवाल किए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने मोनटरिंग की बात कही। मैं खुद समझती हूं कि मानीटरिंग सेल्स वैसे तो हैं स्टेट गवर्नमेंट की लेवल पर भी हैं, सेंट्रल लेवल पर भी हैं, लेकिन उनको और मजबूत करने की जरूरत है और उनकी तरह ध्यान दिया जा रहा है कि सेल्स खोले और बाकायदा उनकी मानीटरिंग हो जो काम फौरन हों और उनमें इंप्रूवमेंट हो।

जहां तक सोशल फारेस्ट्री का सवाल है उसमें 10 परसेंट रखा गया है और उसको देखा जा रहा है कि और क्या हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट का काम है, उसमें उनका इनवलावमेंट हो, उसका विकास हो, इसीलिए ये विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम भी चाहते हैं कि पंचायत एक वायेबल युनिट बने। उसके जरिये से गांव का डवलोपमेंट हो और इसके लिये नई-नई स्कीमें चलाई जा रही हैं। साथ ही हमारी जो लेंडलैस एम्प्लायमेंट गारण्टी स्कीम है इसमें और भी योजना बढ़ा रहे हैं। रूरल एम्प्लायमेंट गारण्टी प्रोग्राम में भी एम्प्लायमेंट का सिलसिला आ जाता है। रोज नई स्कीम निकल रही है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये और अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये।

SHRIMATI MONIKA DAS: Mr. Deputy Chairman, Sir, our hon. Minister has

said that they have formed some monitoring cells at the State, district and block levels. What I find in mnay rural areas under the National Rural Employment Programme is that due to lack of urgency on the part of the officials, at various levels, proper attention is not being given to this. In spite of the monitoring cells, they are not succeeding with this National Rural Employment Programme. What steps the Government is going to take to see that the Rural Employment Programme gets properly implemented?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, it is the responsibility of the State Governments to look after the interests of the rural people, and they have their implementing machinery. (*Interruptions*).

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, the success of a programme like this should be judged more by the employment generated in terms of the million mandays produced than the utilisation of funds because the unit cost of employment per mandays generation has been increasing year after year. And it will also increase further in the years to come. Keeping this experience in view, will the Minister assure that at least in the Seventh Plan more money will be earmarked for this Programme so that the net employment generated will not be less than what it has been achieved during the Sixth Plan?

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया मैनडेज के बारे में तो मैं बताना चाहती हूं कि मैनडेज का काम दूसरे ढंग से पूरा किया जा रहा है। मैंने जैसा अभी बताया कि जहां जहां मिनिमम एग्रीकल्चर वेजिज बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा एमाउंट फिक्स है, उसी हिसाब से वेजेज देते हैं। उस में कमी भी हो जाती है। इस सिलसिले में मैं बताना चाहती हूं कि 1984-85 में हमारा टारगेट 600 मिलियन मैनडेज का है, 300 मिलियन मैनडेज अंडर दिस स्कीम एंड 300 मिलियन मैनडेज अन्डर रूरल एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम इस तरह से 600 मिलियन मैनडेज का टारगेट हमारा इस साल का है। मैं समझती हूं हम इसे जरूर पूरा करेंगे सेवथ प्लान के बारे में बाद में बताऊंगी।

SHRI DEBA PRASAD ROY: I would like to bring one point to the hon. Minister's notice through you, Sir, that the concept of giving employment to the rural poor people by implementing the IRDP is the most sensitive programme today. But the greatest lacuna of the Programme is that while giving the benefits to the poorer people, the banks consider the credibility of the beneficiary to be able to repay the loan. And they also examine whether the beneficiaries are defaulters or not. If the concept of the Programme is to cover the poorest of the poor, the poorest of the poor has no option but to be a defaulter because he must have taken loan either from the co-operative bank or from some other banks to the extent of Rs. 1,000 or Rs. 2,000 which stands in the way of getting benefit under the IRDP. My humble suggestion is....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This point does not arise from this question.

SHRI DEBA PRASAD ROY: This is about rural employment. The discussion has been raised for rural employment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not for loan. You are raising a different question.

SHRI DEBA PRASAD ROY: The concept of the IRDP is to give employment by putting up industries and schemes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, you can direct this question to some other Ministry and not to this Ministry.

SHRI DEBA PRASAD ROY: There are four or five schemes to give employment to rural poor. IRDP is one of them. NREP is one of them. I know all these things. But the intention of the IRDP is to give tmployment...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot mix up all.

SHRI DEBA PRASAD ROY: It is a part of the Rural Development Ministry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Put some other question.

SHRI DEBA PRASAD ROY: Can I not bring this problem to the notice of the House?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bring it when you can put the question to the concerned Minister. Not at this time.

SHRI DEBA PRASAD ROY: Is IRDP not a part of the rural development?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are on a particular question. Not on a topic like that.

SHRI DEBA PRASAD ROY: The question is of giving employment to the rural people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put some other question relating to this question.

SHRI DEBA PRASAD ROY: This has been the problem in the rural areas.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That problem can be taken care of some other time.

SHRI DEBA PRASAD ROY: Let me have the opportunity of stating this problem now. It is all pertaining...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Find some opportune moment to raise this problem.

SHRI DEBA PRASAD ROY: In Manipur in one district called Chora Chandpur only subsidy is paid to the beneficiaries; on loan is paid to them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please understand the question. You have not followed the question. This question does not pertain to subsidy or loan. Yes, Mr. Yadav.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास में रोजगार देने का जो काम है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गांवों में गरीब लोगों को काम मिले और काम के साथ-साथ जो लिंक रोड्स होनी चाहिए, जो अभी गांवों में नहीं हैं, उनके संबंध में आप क्या कर रहे हैं ? अभी स्थिति यह है कि गांवों में बहुत इंटिरियर में जहां पर बिलकुल भी रोडस नहीं हैं वहां पर चोरियां और डकैतियों तथा अनलाफुल काम बहुत होने लगे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस रोजगार देने की स्कीम में जो कच्ची सड़कों को पक्की बनाने और नई सड़क का निर्माण करने का काम है, क्या उसके लिए आपने कोई योजना बनाई है ? अगर आपने कोई योजना बनाई है तो क्या यह भी सही है कि उसमें आपको पूरी सफलता नहीं मिल रही है ? क्या आप उसके लिए कोई मूल्यांकन समिति या इसी तरह की कोई अन्य चीज बनाकर उसकी परीक्षा करेंगे ताकि यह पता लग सके कि इसमें किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है और जिससे आपको काम में सफलता मिल सके लोगों को रोजगार मिल सके, इस संदर्भ में एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इस काम में जिन अधिकारियों को जिम्मेवारी दी है उन अधिकारियों को इस बात का प्रशिक्षण नहीं होता है कि रोजगार कैसे दिया जाय और गांवों में रोजगार किन-किन कामों के लिए देना होगा। उदाहरण स्वरूप गांवों में लघु उद्योग के क्षेत्र में पहले जो चमड़े का, कपड़े का, जूते का और तेल बनाने आदि का काम होता था वह बंद होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि इनके दूसरे पैटर्न को देखकर गांवों में लोगों को रोजगार दिया जा सके ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति जी, मैं बिलकुल माननीय सदस्य से सहमत हूं कि गांवों की जिन्दगी में गांव वालों के लिए सड़कों की बहुत अहम जरूरत है। गांवों के लिए सड़के बहुत ही अहम चीज है। गांवों में पहले सड़के बनें, उसी के लिए सारी स्कीम बनाई जा रही है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मूल्यांकन किया जाय। मोनिटरिंग सैल और मोनिटरिंग स्कीम इसीलिए है कि उसका मूल्यांकन किया जा सके और उसकी कमियों को दूर किया जा सके। तीसरी चीज उन्होंने आफिसरों के बारे में कही कि उनको ट्रेनिंग नहीं होती है। एक स्कीम हम बहुत जल्दी ही शुरु करने जा रहे हैं जिसमें उनका प्रशिक्षण और उनकी ट्रेनिंग उस काम में हो जिस काम को वे करने जा रहे हैं और उसकी एक रूपरेखा बनाई जाय।

श्री राम भगत पासवान : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि समाज में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे है उनके अन्दर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए आपने एन० आर० ई० पी० और आई० आर० ई० पी० और टारजन जैसी स्कीमें भी बनाई हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल सके, इन योजनाओं के अन्तर्गत आपने कितना खर्च किया है, इन योजनाओं में कितने हरिजनों और आदिवासियों को रोजगार दिया गया है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने एक नया सवाल किया है। यह सवाल एक परटिकुलर स्कीम के बारे में है। इसके लिए मुझे अलग से नोटिस की जरूरत होगी।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपसभापति महोदय, सरकार ने गांवों के अन्दर ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री सीताराम केसरी : पहले गमछा ठीक कीजिये।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : गमछा गांव का प्रतिनिधित्व करता है।

जहां 1951 में किसानो की संख्या 57 फीसदी थी वहां 1981 में 47 फीसदी हो गई और खेतिहर मजदूरों की संख्या 1951 में 14 फीसदी थी जो कि 1981 में 25 फीसदी हो गई। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि खेती पर निरन्तर भार बढ़ता जा रहा है और खेतिहर मजदूरों की संख्या गांवों में बढ़ती जा रही है तथा सीमा पर के जो किसान है, जो सीमान्त किसान हैं वे अपनी जमीन बेच रहे हैं और खेतिहर मजदूर हो जाते हैं और इसलिये गांवों मे निरन्तर खेतिहर मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिये इन खेतिहर मजदूरों के लिये गांवों में रोजगार खुलने चाहिए। साथ ही साथ जो किसान खेत पर से बेकाम होते जा रहे हैं उनको खेत पर से बेकाम नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इसको रोकने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जब तक गांवों में रोजगार नहीं होगा और अभी जगदम्बी प्रसाद यादव जी ने कहा कि खेतिहर मजदूर भी गांव छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां रोजगार नहीं मिलता है।

श्री उपसभापति आप सवाल पूछिये।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपसभापति जी, अभी हमारा उत्तरी विहार

का इलाका बाढ़ से बरबाद हो गया है। वहां पर ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दरभंगा मधुबनी इत्यदि जगहों पर तुरन्त कोई काम नहीं दिया गया है। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछड़े, आदिवासी, हरिजन और समाज के सबसे कमजोर तबके को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन उनको यह लाभ नहीं मिल पाता है और बड़े बड़े लोग लूट कर खा जाते हैं। इस बात के लिये जब तक सरकार कोई जांच नहीं करेगी और उसको रोकने के लिये उचित कदम नहीं उठायेगी तब तक सरकार चाहे जो भी योजना चलाये, उन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई : महाशय जी, जितनी योजनायें चलती हैं ग्रामीण रोजगार के लिये उनका मकसद यही है कि जो खेतिहर मजदूर है, वीकर सैक्शन हैं; उनको रोजगार दिलाया जा सके जो वहां उद्योग धंधे खोलते हैं उनकी भी यही मंशा है कि उनके जरिये वहां के दूसरे लोगों को रोजगार मिल सके, वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें।

*285. [*The questioner (Shri Suraj Prasad) was absent. For answer,* vide col. 36 infra.]

*286. [*The questioner (Dr. Shrimati Najma Heptulla) was absent. For answer,* vide *col.* 36-37 infra.]

Excavation work at Vikramashila

†*287. DR. LOKESH CHANDRA:
SHRIMATI USHA MALHOTRA:

Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) what steps Government propose to take to preserve the excavated site of Vikramashila; and

(b) by when the excavation work is likely to be resumed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. K. THUNGON): (a) The Survey has already taken up necessary steps for the preservation of the excavated site at Antichak also known as Vikramshila. The work is in progress.

(b) There is no proposal to resume the excavation work for the present.

डा० लोकेश चन्द्र : उपसभापति महोदय, 1960 में पटना विश्वविद्यालय ने विक्रमशिला की खुदाई आरम्भ की थी और 12 वर्ष पीछे 1972 में पुरातत्व विभाग ने इस खुदाई को अपने हाथ में ले लिया और वहां पर डा० बी० एस० वर्मा को निरीक्षक नियुक्त किया। लेकिन दो वर्षों पहले निरीक्षक को हटा लिया गया उनके हटने से विक्रमशिला की खुदाई में जो सामान मिला है वह नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुपरिटेन्डेन्ट, आर्कियोलाजी विक्रमशिला में कब तक नियुक्त हो जायेगा और वित्तीय निधि की कमी को पूरा करने के लिये मंत्री महोद क्या प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री पी० के० थुंगन : डिप्टी चेयरमैन साहब, जो सदस्य महोदय ने कहा है कि सुपरिटेन्डेन्ट, आर्कियोलाजी वहां पर नहीं हैं, यह सच बात है। यह पोस्ट पिछले डेढ़ सालों से खाली है। चूंकि वहां पर खुदाई का काम 1982–83 के सीजन में खत्म हुआ था, उस पोस्ट की जहां ज्यादा जरूरत थी, वहां पर इस्तेमाल करने के लिये हम्पी एक जगह है, जहां पर खुदाई चल रही है, वहां

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Lokesh Chandra.